(8) मैं, इसलिए, मान लेता हूं कि उप-धारा 23 (1-ए) और उप-धारा (2) द्वारा क्रमशः परिकल्पित अतिरिक्त राशि और सोलैटियम केवल बाजार मूल्य पर देय हैं, जैसा कि धारा 23 के खंड 1 के तहत निर्धारित किया गया है और इस उप-धारा के तीसरे खंड के तहत निर्धारित राशि पर नहीं। अधिनियम की धारा 28 द्वारा परिकल्पित ब्याज के रूप में ब्याज, निश्चित रूप से, मुआवजे की पूरी राशि पर देय है, अर्थात्, बाजार मूल्य और धारा 23 के उप-धारा (1) के तीसरे खंड के तहत मूल्यांकन किया गया नुकसान, जैसा कि अनिवार्य रूप से शामिल है बाजार मूल्य और अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण एक ज़मींदार को देय नुकसान।

(९) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, राज्य अपील को याद किया जाता है, लेकिन लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है और जमींदार-दावेदारों द्वारा दायर क्रॉस-ऑब्जेक्ट्स की अनुमति है, जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, आनुपातिक लागत के साथ।

आर.एन.आर.

जज उजागर सिंह

देव रतन, -पुटिशनर।

हरियाणा के बनाम, -सोन्सेंटेंट।

1988 का क्रिमिनल रिवीजन नंबर 243

29 जुलाई, 1988,

हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम (VII 1975) एसएस। 3, 7, 10 और 11-कोड का आपराधिक प्रक्रिया (1974 का 11) एसएस। धारा 7 के तहत धारा 7 के तहत 248 और 468-ऑफेंस सजा-लिमिटेशन-लिमिटेशन के साथ संज्ञानात्मक-कॉम-लिमिटेशन के साथ-साथ धारा 7-प्रॉसेस्यूशन के तहत अपराध का मिशन-ट्रायल कोर्ट फ्रेमिंग चार्ज के तहत धारा 10-अभियुक्त के तहत आरोपित किया जा सकता है कि क्या इसके बाद राज्य दाखिल करना आपराधिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। डिस्चार्ज-रिवीजन के आदेश के खिलाफ, चाहे सक्षम।

आयोजित, कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार, 1973 आरोप को तैयार करने के बाद यदि मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी नहीं पाया है तो उसे बरी करने का एक आदेश रिकॉर्ड करना होगा और अगर वह आरोपी को दोषी पाता है, तो आरोपी है। सजा के सवाल पर उसे सुनने के बाद सजा सुनाई जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट के लिए कोई विकल्प नहीं है कि वह बरी के आदेश की तुलना में किसी अन्य आदेश को पारित करे, अगर वह आरोपी को दोषी नहीं पाता है। इसलिए यह आयोजित किया जाना चाहिए कि चार्ज को फंसाने के बाद डिस्चार्ज का एक आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। (पैरा 7)।

आयोजित किया गया है, कि एक बार निचली पुनर्विचार अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंच गई है कि डिस्चार्ज ऑर्डर एक बरी होने की राशि है, इस मामले से निपटने के लिए इसके आगे कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि बरी होने के कारण राज्य द्वारा बरी के खिलाफ अपील में चुनौती दी जा सकती है जो उच्च के समक्ष है। अदालत।

(पारस 6 और 7)

हेल्ड, कि क्रिमिनल प्रक्रिया के संहिता की धारा 468 के तहत सीमा। 1973 और कोड के निम्नलिखित खंड एक अपराध से संबंधित हैं, जो कि प्राइमा फेशियल है, न कि किसी अपराध के लिए जो अंततः प्रतिबद्ध पाया गया है।

(पैरा ६)

याचिकाकर्ता के लिए के एस थापर, अधिवक्ता।

वी। एस। तोमर, वकील, प्रतिवादी के लिए।

प्रलय

जज उजागर सिंह

यह याचिका लगभग भर्ती किए गए तथ्यों से उत्पन्न होती है। देव रतन याचिकाकर्ता 14 कनाल 11 मार्लस के मालिक थे, जो कृषि भूमि के थे। वह,

हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र अधिनियम, 1975 के विनियमन की धारा 3 के प्रावधानों के तहत निदेशक से किसी भी लाइसेंस के बिना, 1975 (इसके बाद "विकास अधिनियम" कहा जाता है), आवासीय भूखंडों को उकेरा और प्रत्येक को चार में से प्रत्येक में 16 बिस्वास का एक क्षेत्र बेच दिया वेंडीज, अर्थात्, मोहिनी देवी, कृष्णा, राम भरोस और बृज लाल; कुल क्षेत्र बेचा गया, 20 नवंबर, 1981 को निष्पादित चार अलग-अलग बिक्री-डिड्स, 3 बीघा 4 बिस्वास में आए। निदेशक की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, जैसा कि विकास अधिनियम की धारा 11 में प्रदान किया गया है, जिला टाउन प्लानर, करणल ने 8 फरवरी को औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई थी। । विकास-मानसिक अधिनियम की धारा 10 के तहत बनाया गया है और याचिकाकर्ता को तदनुसार श्री पी। एल। खांडुजा, तत्कालीन उप-विभाजन के न्यायिक मजिस्ट्रेट, पनीपत, ने 9 नवंबर, 1984 को आदेश दिया। 16 जनवरी, 1986 तक 3 गवाहों की जांच की गई जब याचिकाकर्ता की ओर से एक आवेदन उनके निर्वहन के लिए किया गया था। आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि विकास अधिनियम की धारा 9 का केवल कॉन-ट्रैवेशन शामिल था और विकास अधिनियम की धारा 10 के तहत छह महीने की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडनीय था । उस आवेदन में यह प्रार्थना की गई थी कि उक्त धारा 9 का उल्लंघन करने के रूप में प्रतिबद्ध किया गया था और अपराध छह महीने के कारावास के लिए दंडनीय था, अभियोजन पक्ष को संहिता की धारा 468 के प्रावधानों द्वारा रोक दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने श्री धरम पाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पैनीपत की अध्यक्षता की, दोनों पक्षों के लिए वकील की सुनवाई के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विकास अधिनियम की धारा 9 का केवल उल्लंघन शामिल था और अपराध केवल दंडनीय था। छह महीने की कैद, अभियोजन पक्ष को संहिता की धारा 468 के प्रावधानों द्वारा रोक दिया गया था।

(२) राज्य ने इस मामले को संशोधन में लिया, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, करणल द्वारा सुना गया था, और तर्क-मांद की सुनवाई के बाद यह उस अदालत द्वारा आयोजित किया गया था: (i) कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप को धारा 10 के तहत फंसाया गया था। धारा 7 के उल्लंघन के लिए विकास अधिनियम, और, जैसा कि अधिकतम दंड में प्रदान किया गया था, वह 3 साल था, सीमा के बार का सवाल नहीं उठता है, और (ii) कि ट्रायल कोर्ट के पास इस मामले को लेने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। चार्ज को फ्रेमिंग, उक्त आरोप से याचिकाकर्ता के निर्वहन के लिए उक्त याचिका, और, वास्तव में, डिस्चार्ज के आदेश के रूप में एक बरी होने की राशि थी।

(३) याचिकाकर्ता ने इस आपराधिक संशोधन को चुनौती के लिए स्थानांतरित कर दिया है- ट्रायल कोर्ट के आदेश को अलग करने और रिट्रियल

के लिए मामले को हटाने के लिए निचली पुनर्विचार अदालत के आदेश को निगलना।

(४) याचिकाकर्ता के लिए वकील के रूप में राज्य के वकील को भी लंबाई में सुना गया है और मैं मामले के तथ्यों से भी गुजरा हूं।

(५) तथ्यों और कानून लागू होने वाले कानून पर चर्चा करने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि संहिता के अध्याय १ ९ में धारा २३ of सेक्शन २४३ से धारा २४३ और उक्त वर्गों ने मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों के परीक्षण के साथ काम किया, पुलिस रिपोर्ट और एक नज़र पर स्थापित किया गया इन खंडों में स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करना होगा कि प्रभारी को फ्रेम करने से पहले औपचारिकताओं से संबंधित संहिता की धारा 207 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। विचार करने के बाद- पुलिस की रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों को कोड की धारा 173 के तहत और इस तरह की परीक्षा देने के बाद, यदि कोई हो, तो आरोपी के रूप में मजिस्ट्रेट आवश्यक सोचता है और अभियोजन और अभियुक्त को एक अवसर देने के बाद भी। सुना जा रहा है, अगर मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप पर विचार आधारहीन करता है , वह अभियुक्तों का निर्वहन करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को रिकॉर्ड करेगा। इन दो कदमों को स्पष्ट रूप से पूर्वसर्गों द्वारा उठाया गया था- वर्तमान पीठासीन अधिकारी के सोर जैसा कि ऊपर कहा गया था और, सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, वर्तमान पीठासीन अधिकारी के पूर्ववर्ती इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता ने एक अपराध के तहत एक अपराध किया था। उक्त अध्याय, जिसे वह कोशिश करने के लिए सक्षम था और वह याचिकाकर्ता को लिखित रूप में फंसाए गए चार्ज के लिए पर्याप्त रूप से दंडित कर सकता था, जिसके लिए याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया गया था। इसके बाद, अभियोजन के सबूत के लिए तीन या चार अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई। कार्यवाही के उस चरण में, याचिकाकर्ता को छुट्टी देने का कोई सवाल नहीं था। अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच करने का चरण अभी तक खत्म नहीं हुआ था कि यह विवादित आवेदन उपरोक्त प्रार्थना के साथ दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष के सबूतों को बंद करने के बाद, याचिकाकर्ता को रक्षा में अग्रणी सबूतों के लिए एक अवसर प्राप्त करना था और वहाँ- मजिस्ट्रेट को तर्कों को सुनने के बाद और मामले को या तो दोषी ठहराने और सजा सुनाकर या उसे बरी करने से मामले का फैसला करना था। श्री धरम पाल की अध्यक्षता में ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता का निर्वहन करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से परे चला गया और मुझे नहीं लगता कि आदेश को पारित करने का कारण आनंदमय अज्ञानता पर आधारित है। श्री धरम पाल को इस आदेश को पारित करने से पहले लगभग

तीन साल तक न्यायिक सेवा का अनुभव था और यह विश्वास करना संभव नहीं है कि उन्हें पुलिस रिपोर्टों के आधार पर वारंट मामलों के परीक्षण के लिए इन प्रावधानों के बारे में नहीं पता था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अभियोजन पक्ष या अदालत के आदेश से बंद नहीं किया गया था और यह तथ्यों से स्पष्ट नहीं है कि उसे निर्वहन के आदेश को पारित करने के लिए क्या राजी किया गया था। यदि उन्हें उक्त आवेदन में सुझाए गए जमीन पर मामला तय करना था, तो याचिकाकर्ता को बरी कर दिया जाना था और इस मामले में उन्होंने किया नहीं है।

(६) निचली रिविजनल कोर्ट ने समझदारी से इस मामले से निपटा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि डिस्चार्ज ऑर्डर राशि- एड को एक बरी करने के लिए। इस निष्कर्ष पर आने के बाद, वह एक आपराधिक संशोधन में मामले से निपट नहीं सका क्योंकि बरी को बरी के खिलाफ अपील में राज्य द्वारा चुनौती दी जा सकती है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष है। ट्रायल कोर्ट की अध्यक्षता करने वाले श्री धरम पाल द्वारा की गई एक और पेटेंट त्रुटि यह थी कि धारा 468 के तहत सीमा और संहिता के निम्नलिखित खंडों में एक अपराध से संबंधित है, जो प्राइमा फेशियल है और न कि अपराध के लिए जो अंततः है। पाया गया कि प्रतिबद्ध है। इस मामले में, अपराध प्राइमा फेशियल को तीन साल की कारावास के साथ दंडनीय था और पुलिस की रिपोर्ट निश्चित रूप से सीमा में थी, जैसा कि लोअर रिविजनल कोर्ट द्वारा पाया गया था। राज्य लगता है कि एक संशोधन दायर करने के लिए गुमराह किया गया है क्योंकि आदेश पारित किया गया था, बरी होने का नहीं बल्कि एक निर्वहन का था और आदेश ने भी मामले के तथ्यों को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, जब पुलिस रिपोर्ट दायर की गई थी, जैसे कि क्या आरोप था किसी भी गवाह की जांच की गई है या नहीं, इसके बारे में भी कहा गया है या नहीं। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आवेदन को स्वीकार करके और याचिकाकर्ता का निर्वहन करके इन सवालों पर चुप्पी देखी।

(7) उपरोक्त चर्चा के साथ, मैं इस विचार से हूं कि संहिता के धारा 248 के प्रावधानों के अनुसार, आवेश के अनुसार, आवेश के रूप में एक बरी होने के लिए डिस-चार्ज ऑर्डर की राशि थी दोषी, उसे बरी करने का एक आदेश रिकॉर्ड करना होगा और अगर वह आरोपी को दोषी पाता है, तो आरोपी को सजा के सवाल पर उसे सुनने के बाद सजा सुनाई जानी चाहिए। यदि वह आरोपी को दोषी नहीं पाता है, तो उसे बरी के आदेश के अलावा किसी भी अन्य आदेश को पारित करने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार जब निचली रेविसिजनल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि डिस्चार्ज ऑर्डर एक बरी हो गया है, तो इस मामले से निपटने के लिए इसका कोई और अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(8) मामले के इस दृष्टिकोण में, इस याचिका की अनुमति है और निचली पुनर्विचार न्यायालय के डेर को अलग रखा गया है। यदि राज्य ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देना चाहता है, तो उसे इस अदालत के समक्ष एक आपराधिक अपील दायर करनी होगी और यदि राज्य की सलाह दी जाती है तो देरी की तलाश करनी होगी।

आर.एन.आर.

जज एम. एम. पुंछी और अमरजीत चौधरी

अवतार कृष्ण सूद और एक और, -पुटिशर। बनाम

हरियाणा और अन्य राज्य, -सोन्सेंटेंट्स।

1988 के सिविल रिट याचिका संख्या 3989

4 अगस्त, 1988।

हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट (1977 का XIII)- एक विशेष क्षेत्र में आवासीय भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन- इस तरह के आवंटन-औपचारिक आवंटन पत्रों के लिए तैयार किए गए हैं जो उस विशेष क्षेत्र में उपलब्ध भूखंडों को जारी नहीं किए गए हैं। सरकार की कार्रवाई।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Avtar Krishan Sood and another *v.* State of Haryana and others
(M. M. Punchhi, J.)

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा